+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(23 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिका ने अपने शीत युद्ध कालीन 'पनडुब्बी जासूसी कार्यक्रम' को पुनर्जीवित किया
- अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों को 'स्टेपल वीजा' दिए जाने के विरोधस्वरूप खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन यात्रा रद्द की
- "भारत में अलगाववादियों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों के गठजोड़" से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं

अमेरिका ने अपने शीत युद्ध कालीन 'पनडुब्बी जासूसी कार्यक्रम' को पुनर्जीवित किया:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिकी नौसेना 1950 के दशक के बाद से अपने शीर्ष-गुप्त समुद्री निगरानी नेटवर्क में सबसे बड़ा बदलाव कर रही है क्योंकि चीन की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि और नई प्रौद्योगिकियां तेजी से समुद्री युद्ध को नया आकार दे रही हैं।
- चीन की अपनी भी ऐसी ही योजनाएं हैं।

'थिएटर अंडरसी सर्विलांस कमांड (TUSC)' क्या है?

- सिएटल से 50 मील उत्तर में व्हिडबी द्वीप पर अमेरिकी नौसेना का एक निगरानी स्टेशन है। वर्षों तक, इसे व्हेल गतिविधियों पर नज़र रखने और समुद्र के बढ़ते तापमान को मापने में व्यस्त रखा गया था।
- पिछले अक्टूबर में, नौसेना ने यूनिट को एक नया नाम दिया जो उसके वर्तमान मिशन को बेहतर ढंग से दर्शाता है: "थिएटर अंडरसी सर्विलांस कमांड"।
- योजनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, व्हिडबी द्वीप सुविधा में जासूसी स्टेशन का नाम बदलना एक बहुत बड़ी अमेरिकी सैन्य परियोजना की ओर इशारा है : शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका के पनडुब्बी रोधी जासूसी कार्यक्रम का सबसे बड़ा पुनर्निर्माण आयोजित करना।
- इंटीग्रेटेड अंडरसीज सर्विलांस सिस्टम (IUSS) के नाम से जाने जाने वाले अरबों डॉलर के प्रयास का पुनरुद्धार तब हुआ है जब चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है, जिससे लोकतांत्रिक रूप से शासित क्षेत्र पर संभावित संघर्ष के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसे बीजिंग अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। .
- नौसेना की समुद्री टोही प्रणाली में सबसे नवीन परिवर्तन पारंपरिक समुद्री निगरानी उपकरणों को लघु और वैश्वीकृत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश है।

- IUSS के अस्तित्व को शीत युद्ध की समाप्ति पर 1991 में ही सार्वजनिक किया गया था, और इसके संचालन का विवरण अत्यंत गुप्त बना हुआ है।

अमेरिकी नौसेना का नवीनतम निगरानी प्रयास के प्रमुख प्रेरक कारक:

- समुद्री शक्ति के रूप में चीन का तेजी से उदय और उसकी आक्रामक नीति: एक समुद्री शक्ति के रूप में चीन का तेजी से उदय और उसके जहाजों द्वारा ताइवान पर हमला करने या तेल पाइपलाइनों और फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट केबलों सहित महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।
- रूसी के खिलाफ नई समुद्री युद्ध रणनीति अपनाने में यूक्रेन की सफलता:
  - ➢ यूक्रेन ने दुश्मन के जहाजों और पुलों पर हमला करने के लिए अपेक्षाकृत सस्ते मानव रहित समुद्री वाहनों का इस्तेमाल किया है।
  - ➢ इस विकास ने ड्रोन हमलों के प्रति बड़े सतही जहाजों की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है, और अमेरिकी नौसेना को अपने आक्रामक अभियानों के लिए इस तकनीक में महारत हासिल करने के साथ-साथ इससे बचाव के तरीके सीखने की आवश्यकता है।

- तकनीकी उन्नति से निगरानी हथियारों की होड़: अंत में, पानी के नीचे अधिक संवेदनशील सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री ड्रोन सहित तेजी से तकनीकी परिवर्तन, बीजिंग और वाशिंगटन के बीच निगरानी हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिकी-चीन नौसेना प्रतिद्वंद्विता:

- उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका और चीन के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा का मुख्य क्षेत्र बन गया है।
- अमेरिकी सहयोगी ताइवान के प्रति बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता, पड़ोसियों के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद और क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति का विरोध, जिसे चीन उत्तेजक मानता है, ने दोनों महाशक्तियों के बीच घर्षण बढ़ा दिया है।

अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों को 'स्टेपल वीजा' दिए जाने के विरोधस्वरूप खेल मंत्री ने चीन यात्रा रद्द की:

क्या मामला है?

- केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश के तीन एथलीटों, सभी वुशु मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा की पेशकश के विरोध में 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी।

- उल्लेखनीय है कि चीन क्षेत्रीय विवाद का हवाला देते हुए लगातार अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टांपयुक्त वीजा देने से इनकार

करता रहा है, जबकि भारत सरकार लोगों को स्टेपल वीजा पर यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है।

स्टेपल वीजा क्या होता है?

- स्टेपल्ड वीजा बस कागज का एक बिना मोहर लगा हुआ टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट के एक पृष्ठ पर पिन या स्टेपल द्वारा जुड़ा होता है और इसे इच्छानुसार फाड़ा या अलग किया जा सकता है।
- यह नियमित वीजा से अलग है जिसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है और मुहर लगाई जाती है।
- चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा बना ली है। इसमें कहा गया है कि वीजा वैध दस्तावेज हैं, लेकिन भारत सरकार ने लगातार इस स्थिति को मानने से इनकार कर दिया है।

चीन ऐसा क्यों करता है?

- पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य प्रकार के आव्रजन नियंत्रण एक राष्ट्र-राज्य और उसकी संप्रभुता के विचार को दोहराते हैं जो अविभाज्य और अनुलंघनीय है। पासपोर्ट अपने धारक की पहचान और नागरिकता का प्रमाण पत्र है।

- चूंकि राष्ट्र-राज्य अपनी सीमाओं में प्रवेश करने या छोड़ने वालों को नियंत्रित करने और विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, इसलिए पासपोर्ट और वीज़ा उनके धारकों को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से और कानूनी सुरक्षा के तहत यात्रा करने का अधिकार देते हैं।
- चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संप्रभुता पर विवाद करता है। यह मैकमोहन रेखा, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा, की कानूनी स्थिति को चुनौती देता है जिस पर 1914 के शिमला कन्वेंशन में ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन में सहमति व्यक्त की गई थी।
- चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अपना दावा करता है। यह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में "ज़ंगनान" कहता है और बार-बार "दक्षिण तिब्बत" का संदर्भ देता है।
- चीनी मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाते हैं, और कभी-कभी मूल रूप से इसे "तथाकथित अरुणाचल प्रदेश" के रूप में संदर्भित करते हैं।

स्टेपल वीजा प्रथा कब से चल रही है?

- अपनी पुस्तक 'आफ्टर तियानानमेन: द राइज ऑफ चाइना' में, भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि राज्य द्वारा संचालित चीनी मीडिया ने 2005 से अरुणाचल प्रदेश को "दक्षिण तिब्बत" के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया।
- चीनियों ने 2006 के अंत में अरुणाचल प्रदेश में सेवारत एक भारतीय सरकारी अधिकारी को वीजा देने से इनकार करके अपने इरादे का संकेत दिया। इसके बाद, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सभी भारतीय नागरिकों को 'स्टेपल्ड' वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की।
- मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल्ड वीजा 2008-09 के आसपास शुरू हुआ प्रतीत होता है।

'भारत में अलगाववादियों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों के गठजोड़' से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं:

चर्चा में क्यों है?

- अगले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित खुफिया एजेंसियों और राज्य आतंकवाद विरोधी दस्तों के प्रमुखों के दो दिवसीय सम्मेलन में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों पर चर्चा होने वाली है।
- यह कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में आई खटास की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें खालिस्तानियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का विषय दोनों देशों के बीच एक दुखती रग के रूप में उभर रहा है।

- बैठक में RAW प्रमुख रवि सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अरुण सिन्हा शामिल होंगे।

खुफिया एजेंसियों की खालिस्तान समस्या से निपटने की रणनीति:

- केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सम्मेलन में दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना चाहती हैं - खालिस्तानी संबंधों वाले लोगों की संपत्तियों पर नजर रखने एवं जब्त करने की आवश्यकता, और राज्य पुलिस बलों के साथ बेहतर समन्वय, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर तरीके से सुरागों को प्रस्तुत किया जा सके।
- वर्तमान में, NIA गैंगस्टरों, आतंकी गुर्गों और प्रतिबंधित खालिस्तान संगठनों के बीच सांठगांठ के संबंध में दर्ज लगभग 10 मामलों की जांच कर रही है। इनमें से अधिकांश मामलों में आरोपी पहले से ही भारत की जेलों में बंद हैं, लेकिन उनके सहयोगी या संचालक कनाडा, पाकिस्तान आदि में हैं।
- उन्हें पकड़ने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ-साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के साथ समन्वय किया जा रहा है।
- एनआईए 1993 के मुंबई विस्फोटों से पहले के युग, जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म उद्योग के सदस्यों के बीच व्यापक संबंध सामने आए थे, की तर्ज पर गैंगस्टरों और

गायकों, कबड्डी खिलाड़ियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है।

एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता क्यों है?

- इस पर एक अधिकारी ने खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के कनाडा स्थित नामित आतंकवादी अर्शदीप सिंह गिल का उदाहरण दिया। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस भी उनके खिलाफ काम कर रही है और एनआईए भी कई मामलों की जांच कर रही है।
- आदर्श रूप से, दोनों जांच टीमों को एक साथ समन्वय करना चाहिए और मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करते समय एक ही पृष्ठ पर नहीं होने से उनकी जांच को नुकसान हो सकता है।
- गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों में सक्रिय आतंकी टीमों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के बीच सूचना, अलर्ट और आतंकी इनपुट के बेहतर आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया।